पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

मोहम्मद शमीम

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

2021 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 8978

10 अगस्त 2023

(माननीय न्यायमूर्ति श्री मधुरेश प्रसाद)

विचार के लिए मुद्दा

- क्या सेवानिवृत्ति के बाद पारित बर्खास्तगी आदेश सही है या नहीं?

हेडनोट्स

सेवा कानून—बर्खास्तगी—सेवा से—याचिकाकर्ता की बर्खास्तगी का आदेश सेवानिवृत्ति के बाद पारित किया गया—याचिकाकर्ता के खिलाफ बिहार पुलिस नियमावली, 1978 के नियम 825 ए के तहत गलत तरीके से कार्रवाई की गई—मनुआ, 1978 वर्दीधारी कर्मियों पर लागू होता है—याचिकाकर्ता एक अनुसचिवीय कर्मचारी था—कर्मचारी पर बर्खास्तगी या सेवा समाप्ति का दंड तब तक लगाया जा सकता है, जब तक वह सेवा में है—सेवानिवृत्ति प्राप्त करने पर, नियोक्ता अनुशासनात्मक नियंत्रण खो देता है, क्योंकि कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद स्वामी-सेवक संबंध समाप्त हो जाता है।

निर्णय: 1935 के नियमों के प्रावधानों के तहत अनुसचिवीय अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की आवश्यकता—अनुसचिवीय अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार न केवल स्वाभाविक रूप से क्षेत्राधिकारविहीन है, बल्कि 1978 के नियमों के नियम 824 ए (सी) में निहित स्पष्ट प्रक्रिया के भी विपरीत है—बर्खास्तगी की सजा का आदेश, याचिकाकर्ता के सेवानिवृत्त हो जाने के बाद—जिस समय सजा का आदेश जारी किया गया था, याचिकाकर्ता पहले ही सरकारी कर्मचारी नहीं रह गया था क्योंकि वह चार (4) महीने पहले सेवानिवृत्त हो चुका था—इसलिए, प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता पर अनुशासनात्मक नियंत्रण खो दिया था—आक्षेपित आदेश याचिकाकर्ता के सेवानिवृत्त हो जाने के बाद जारी किया गया है—बर्खास्तगी का आदेश कानून की दृष्टि में टिकने योग्य नहीं था—आक्षेपित आदेश रद्द—याचिकाकर्ता सभी परिणामी लाभों का हकदार है—याचिका स्वीकार की गई। **(कंडिका 7 से 11)**

न्याय दृष्टान्त

कुछ भी नहीं

अधिनियमों की सूची

सेवा कानून, बिहार पुलिस मैनुअल, 1978; बिहार अधीनस्थ सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1935; भारत का संविधान, 1950।

मुख्य शब्दों की सूची

सेवानिवृत्ति; बर्खास्तगी आदेश; दंड, स्वामी-सेवक संबंध; अनुशासनात्मक नियंत्रण

प्रकरण से उत्पन्न

याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति के बाद प्राधिकरण द्वारा पारित बर्खास्तगी आदेश से।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ता की ओर से**:** श्री दीनू कुमार**,** अधिवक्ता।

राज्य की ओर से**:** श्री शिव शंकर प्रसाद**,** एससी-8।

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: आभाष चंद्र, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2021 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 8978

==

मो. शमीम, पिता - स्वर्गीय मो. यूनुस, निवासी गांव - इस्लामपुर, थाना तथा डाकघर तथा जिला -मुज़फ़्फ़रपुर

.... अपीलकर्ता/ओं

बनाम

1. मुख्य सचिव के माध्यम से बिहार राज्य, बिहार सरकार
2. बिहार के पुलिस महानिदेशक सह पुलिस निरीक्षक
3. पुलिस महानिरीक्षक, तिरहुत
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर

....उत्तरदाता/ओं

==

उपस्थितिः

याचिकाकर्ता/ओं के लिए	:	श्री दीनू कुमार, अधिवक्ता
राज्य के लिए	:	श्री कमलेश किशोर, अधिवक्ता

==

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री मधुरेश प्रसाद

मौखिक निर्णय

दिनांक : 10-08-2023

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

2. याचिकाकर्ता पुलिस बल में 'लिपिक' था। उसे नौकरी से बर्खास्त करने की सजा दी गई है। याचिकाकर्ता के इस तर्क के मद्देनजर कि यह आदेश अधिकारक्षेत्र से बाहर है, बर्खास्तगी के आदेश की आक्षेपित की गई है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर के कार्यालय में लिपिक के पद पर तैनात था। वहाँ तैनात रहते हुए, उन्हें 12-04-2014 को एक ज्ञापन दिया गया, जिसका शीर्षक था ज्ञापन संख्या 1356 (अनुलग्नक-2), जिसमें सेवा से बर्खास्तगी के संबंध में उनकी टिप्पणी मांगी गई थी। याचिकाकर्ता को पंद्रह (15) दिनों के भीतर अपना जवाब देना आवश्यक था। ऐसा प्रतीत होता है कि यह कार्यवाही इस आरोप पर की गई है कि एक मामले की जाँच में उनकी भूमिका अवैध और अनियमित मानी गई थी। याचिकाकर्ता के विरुद्ध बिहार पुलिस नियमावली, 1978 की नियम 825 ए के अंतर्गत कार्यवाही की गई है।(जिसे यहाँ आगे "1978 नियम" कहा गया है)

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ पूरी कार्यवाही अधिकार क्षेत्र के बिना एक असक्षम प्राधिकारी द्वारा की जा रही है। चूँकि, याचिकाकर्ता अनुसचिवीय संवर्ग का सदस्य है, इसलिए नियम 824 ए(सी) के अनुसार याचिकाकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही केवल बिहार अधीनस्थ सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1935 (जिसे आगे '1935 नियमावली' कहा जाएगा) के अंतर्गत ही की जा सकती थी। हालाँकि, याचिकाकर्ता के विरुद्ध 1978 के नियम 825 ए के तहत कार्यवाही की गई है। प्रक्रिया काफी अलग है, और 1978 के नियम 825 ए का सहारा लेना, 1978 के नियम 824 ए(सी) में निहित प्रावधानों के विपरीत होने के अलावा, याचिकाकर्ता के लिए भी हानिकारक है। 1935 के नियमों के तहत विधिवत गठित कार्यवाही में, प्रक्रियात्मक आवश्यकताएं भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 में निर्धारित प्रक्रिया के अधिक अनुरूप हैं। दूसरी ओर, बिहार पुलिस नियमावली, समान सेवा से संबंधित है जहाँ अपेक्षित आचरण और अनुशासन उच्चतर हैं और प्रक्रियात्मक आवश्यकताएँ 1935 के नियमों के समान स्तर की नहीं हैं।

4. मामले का दूसरा पहलू यह है कि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि कार्यवाही, यद्यपि गलत प्रक्रिया के तहत शुरू की गई थी, परंतु अंततः उसे बर्खास्त करने का दंडात्मक आदेश जारी किया गया, जो दिनांक 24-04-2015 (अनुलग्नक-7) का है, जो याचिकाकर्ता के सेवानिवृत्त होने के लगभग चार (4) महीने बाद जारी किया गया।यह प्रस्तुत किया गया है कि कानून बहुत स्पष्ट है कि किसी कर्मचारी को बर्खास्तगी या सेवा समाप्ति का दंड तब तक दिया जा सकता है जब तक वह सेवा में है। सेवानिवृत्ति प्राप्त करने पर, नियोक्ता अनुशासनात्मक नियंत्रण खो देता है, क्योंकि कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के साथ ही स्वामी-सेवक संबंध समाप्त हो जाता है।

5. ऐसी परिस्थितियों में, यदि नियम अनुमति देता है, तो केवल कार्यवाही समाप्त करने के सीमित उद्देश्यों के लिए प्राधिकरण के लिए याचिकाकर्ता की सेवा जारी रखना संभव है ।हालाँकि, ऐसी प्रक्रिया का सहारा नहीं लिया गया है और इसलिए, आक्षेपित आदेश अवहनीय है।

6. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि पूरी प्रक्रिया 1978 के नियमों के नियम 825 ए के अनुसार पूरी की गई थी और याचिकाकर्ता ने प्राधिकारियों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया के संबंध में कोई आपत्ति नहीं जताई गयी है। निष्कर्ष दर्ज होने

के बाद, केवल दंड आदेश पारित करने के सीमित उद्देश्यों के लिए, मामले को 1978 के नियमों के नियम 825 ए में निहित आवश्यकता के मद्देनजर सक्षम प्राधिकारी को भेजा गया था, जो इस प्रकार है:

> *"यदि सक्षम अधिकारी की राय में विभागीय कार्यवाही में आखिरी आदेश पारित करने के लिए, अपराधी को ऐसी सजा दी जानी चाहिए जिसके लिए वह आदेश पारित करने के लिए सक्षम नहीं है, तो आखिरी कार्यवाही के साथ सभी कागजात उचित माध्यम से उस सजा को देने के लिए सक्षम अधिकारी को भेजे जाएंगे। उदाहरण के लिए, यदि किसी निरीक्षक से संबंधित कार्यवाही में महानिरीक्षक के आदेश की आवश्यकता हो, तो संबंधित सभी कागजात और फाइल उप महानिरीक्षक के माध्यम से महानिरीक्षक को भेजी जाएगी।"*

7. याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति से पहले ही यह *पूर्वनिश्चित* है । यह केवल परिणामी आदेश है जो सेवानिवृत्ति के बाद जारी किया गया है, और इसलिए इन कारणों से, याचिकाकर्ता दंड के आदेश के संबंध में शिकायत दर्ज कराने की स्थिति में नहीं है।

8. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करने पर, यह न्यायालय पाता है कि 1935 के नियमों के प्रावधानों के तहत मंत्रालयिक अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की आवश्यकता 1978 के नियमों के नियम 824 ए (सी) को पढ़ने से ही स्पष्ट हो जाती है। कानून में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पक्षकार ऐसा अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं कर सकते जो अन्यथा प्राधिकरण में निहित न हो। मंत्रिस्तरीय अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार क्षेत्र न केवल स्वाभाविक रूप से अपर्याप्त है,बल्कि 1978 के नियम 824 ए(सी) में निहित स्पष्ट प्रक्रिया के विपरीत भी है। याचिकाकर्ता के विरुद्ध बिहार पुलिस नियमावली के नियम 825 ए के तहत कार्यवाही नहीं की जा सकती थी।

9. मामले का एक अन्य पहलू यह है कि बर्खास्तगी की सजा का आदेश 24-04-2015 का है, जो याचिकाकर्ता के सेवानिवृत्त होने के लगभग चार (4) महीने बाद का है। जिस समय सजा का आदेश जारी किया गया था, उस समय याचिकाकर्ता पहले ही सरकारी कर्मचारी नहीं रह गया था क्योंकि वह चार(4) महीने पहले ही सेवानिवृत्त हो चुका था। इसलिए, प्राधिकरण ने याचिकाकर्ता पर अनुशासनात्मक नियंत्रण खो दिया था। उत्तरदाताओं ने ऐसा कोई नियम/प्रक्रिया नहीं बताया है जिसके तहत सेवानिवृत्ति के बाद बर्खास्तगी का आदेश दिया जा सकता था। उत्तरदाताओं का यह भी कहना नहीं है कि उन्होंने दंडादेश उस समय पारित किया जब याचिकाकर्ता सेवा में था। याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति आयु प्राप्त करने के बाद आक्षेपित आदेश जारी किया गया है। इसलिए, जहाँ

तक बर्खास्तगी/समाप्ति के परिणाम का सवाल है, यह आदेश स्पष्ट रूप से अवहनीय है। यदि किसी भी प्रकार याचिकाकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही करना या उसे दंडित करना आवश्यक था, तो यह कार्य या तो उसे सीमित उद्देश्य से विभागीय जांच हेतु सेवा में बनाए रखकर किया जा सकता था अथवा यदि किसी नियम में प्रावधान हो तो उसकी पेंशन संबंधी सुविधाएँ रोकी जा सकती थीं, जो कि नहीं किया गया। दिनांक 24-04-2015 का विवादित आदेश (अनुलग्नक-7) अवहनीय नहीं है और इसे रद्द किया जाता है।

10. दिनांक 24-04-2015 (अनुलग्नक-7) के आक्षेपित आदेश को रद्द करने के परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता सभी परिणामी लाभों का हकदार है, जिनका भुगतान प्राधिकरण इस आदेश की प्रति प्राप्त होने/प्रस्तुत होने की तिथि से तीन (3) महीने के भीतर करने के लिए बाध्य होगा।

11. तदनुसार, रिट याचिका स्वीकार की जाती है।

(मधुरेश प्रसाद, न्यायमूर्ति)

राज किशोर/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।